



5 परसेंट को नहीं खाने देंगे मलाई, भारत बंद का विरोध

SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के लिए सड़क पर उतरेंगे जीतन राम मांझी

चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ
पटना, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दलितों के बीच ही विवाद बढ़ता जा रहा है। दलित संगठनों के एक समूह ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। लेकिन दलितों जातियों के दूसरे वर्ग ने भारत बंद का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तत्काल लागू करने की मांग की है।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दलितों के आरक्षण में क्रीमी लेयर की मांग का समर्थन करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तत्काल लागू किया जाना चाहिये। मांझी ने आज पटना में दलित वर्ग में शामिल 18 जातियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद 21 अगस्त के भारत बंद के विरोध का एलान किया गया। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से मांग की है कि बिहार सरकार तत्काल दलितों में शामिल बेहद कमजोर जातियों के अलग से आरक्षण की प्रावधान करे, वनां वे सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे।
एनडीए में टकराव
जीतन राम मांझी के एलान से एनडीए के भीतर ही टकराव बढ़ गया है। एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री और एलजेपी(आर) के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा था कि वे दलितों के आरक्षण के भीतर कोटे का विरोध करते हैं और केंद्र सरकार से अपनी बात कहेंगे। वहीं, केंद्र सरकार में ही मंत्री जीतन राम मांझी ने आज दलितों के आरक्षण के भीतर कोटे



की मांग के समर्थन में 18 जातियों की बैठक की और सड़क पर उतरने की चेतावनी दे दी।
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर के आधार पर उपवर्गीकरण लागू करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को यदि बिहार सरकार लागू नहीं करती है तो 18 दलित जातियों के लोग सड़क पर उतरेंगे। दलित वर्ग में शामिल 18 जातियों के

लोग पटना में रैली करेंगे। मांझी ने कहा कि एससी एसटी आरक्षण में जो जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित हैं, उन्हें आरक्षण में उपवर्गीकरण (कोटा में कोटा) कर लाभ दिया जाना चाहिए।
जीतन राम मांझी ने वंचित अनुसूचित जाति-जनजाति मोर्चा , बिहार के बैनर तले मंगलवार को रविंद्र भवन (पटना) में 18 जातियों का सम्मेलन बुलाया। उन्होंने कहा कि आरक्षण में जातियों के

उपवर्गीकरण को यथाशीघ्र लागू कर सुप्रीम कोर्ट की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। इस सम्मेलन में आरक्षण से वंचित मुसहर-भुईयां, डोम, मेहतर तूरी, रजवार, भोक्ता, घुमंतू आदि जातियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
जीतन राम मांझी के सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण का फैसला देकर आरक्षण के भागीदारी से पीछे हट गए समुदायों के लिए सही फैसला लिया है। एससी एसटी आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में बिहार सरकार तत्काल कदम उठाये और एससी-एसटी में उपवर्गीकरण यथाशीघ्र लागू करे। इस सम्मेलन में कहा गया कि एससी एसटी वर्ग में आरक्षण से पीछे छूटे हुए वर्ग को राज्य सरकार तत्काल शिक्षा, नौकरी और योजनाओं के लाभ में प्राथमिकता दे।
भारत बंद का विरोध
दलितों की 18 जातियों के संघ ने कहा है कि वे इस मुद्दे पर 21 अगस्त 2024 को आहूत भारत बंद को नेतृत्व विहीन और अनुचित मानते हैं। ऐसे में सभी 18 जाति के लोग इस भारत बंद में शामिल नहीं होने का संकल्प ले रहे हैं।
मोर्चा की मांगों के समर्थन करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि आज तक आरक्षण की समीक्षा नहीं हुई , जो अविलंब होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि उपवर्गीकरण की बात तो निश्चित करेंगे ताकि 78 साल बाद जिस वर्ग तक सुविधा नहीं पहुँची, उसको भी मौका मिले। मांझी ने कहा कि

संपन्न दलित यह झूठ फैला रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। ऐसा भ्रम फैलाने का हम विरोध करते हैं। आज आजादी के 78 साल बाद जो संपन्न दलित हैं , वे ही आरक्षण के बल पर 95न नौकरी और तमाम सुविधाओं का लाभ लेते रहे हैं।
उन्होंने कहा कि बिहार में हम 18 जाति के लोगों को आरक्षण का आज तक कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है , इसलिए हम मांग करते हैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से कि आरक्षण में उपवर्गीकरण होना चाहिए। बिहार में ऐसी 18 जातियां हैं जिनकी आबादी 10न है उन्हें कम से कम 10न आरक्षण मिलना चाहिए और कुछ संपन्न दलितों के द्वारा आरक्षित खत्म करने की बात कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। वे वही लोग हैं जो वंचित दलितों के विकास के रास्ते को रोकना चाहते हैं। मांझी ने कहा कि वे चाहते हैं कि राज्य सरकार बिहार में भी हरियाणा के तरह आरक्षण में भी वर्गीकरण कर वंचित दलित को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करे।
कार्यक्रम में बिहार मंत्री डॉ संतोष कुमार सुमन ने कहा कि दलितों की 18 जाति के लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए और एकजुटता दिखा करके अपनी ताकत का एहसास करानी चाहिए। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन जो वंचित रह गया है जिसको आज तक आरक्षण का कोई सुविधा नहीं मिली उसकी हम वकालत करते हैं। उनको मौका मिलना चाहिए।

भारत बंद का बिहार में दिखा असर

ट्रेन और वाहनों को रूकवाया, यात्री और परीक्षार्थी दिखे परेशान

चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ
एससी-एसटी समाज और भीम आर्मी ने बुधवार को भारत बंद का ऐलान किया है। इसका असर सुबह से ही कई जिलों में दिखने लगा है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जिलों को अलर्ट भी किया गया है जिसके बाद पुलिस विशेष निगरानी रख रही है। वहीं बुधवार को भारत बंद को सफल बनाने विभिन्न संगठनों के लोग सड़क पर उतरे। कहीं यातायात व्यवस्था बाधित की गयी तो कहीं ट्रेन को रोक कर पटरी पर जमा आंदोलनकारियों ने नारेबारी की। बस-ऑटो नहीं मिलने के कारण यात्री पैदल चलने को भी मजबूर दिखे।
मुजफ्फरपुर में भारत बंद को सफल बनाने के लिए भीम आर्मी के सदस्यों ने 57 को जाम कर दिया है। जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र इलाके के शाहबाजपुर के पास जाम से लोक परेशान हैं।
वहीं मुजफ्फरपुर छपरा न 102 को भी जाम करवा दिया गया है। इस कारण सड़क के दोनों ओर से ट्रक और अन्य वाहनों की लंबी कतार लग गई है। इतना ही नहीं दुकानों को भी बंद करवा दिया गया है।
रेल पुलिस भी अलर्ट, जांच अभियान तेज
भारत बंद के मद्देनजर रेल पुलिस अलर्ट मोड पर है। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर RPF और GRP द्वारा संयुक्त रूप से स्टेशन एरिया एवम यार्ड में फ्लैग मार्च किया गया है। प्लेटफार्म और रेलवे ट्रैक को भी जांच की है। अभी तक सभी सामान्य है।
पटना के बाढ़ में सड़क जाम
पटना के बाढ़ थांना क्षेत्र के मलाही गांव स्थित एनएच पर भारत बंद का नजारा देखने को मिला। भारत बंद कराने सड़क पर उतरे आंदोलनकारियों ने नेशनल हाइवे पर टायर जलाकर सड़क को जाम किया और अपना विरोध जताया। इस दौरान दोनों तरफ वाहन खड़े रहे।
भोजपुर में भारत बंद का दिखा असर
आरक्षण को लेकर देशभर में जारी भारत बंद का असर भोजपुर में भी बुधवार को देखने को



मिला। यहां भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने शहर के प्राइवेट बस स्टैंड के पास सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया। सड़क जाम हो जाने के कारण आरा-पटना मुख्यमार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। माले नेताओं केन्द्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पटरी पर जमा होकर भी प्रदर्शन किया गया और रेल सेवा बाधित की गयी।
सिवान में दिखा भारत बंद का असर
भारत बंद का सीवान में भी असर दिखा। सख्/स्त्र आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के विरोध में सीवान में भी बंद कराया गया। भीम सेना के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जाम किया। शहर की कुछ दुकानें भी बंद करायी गयी। जेपी चौक सहित मुख्य चौराहों को बंद करवाया। बुधवार की सुबह सड़क पर उतरे भीम सेना के कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते दिखे। इस दौरान सिपाही बहाली परीक्षा के परीक्षार्थियों को परेशान देखा गया। वहीं वाहनों की भी कतार सड़क के दोनों ओर लग गयी।
हाजीपुर में भारत बंद का दिखा असर :हाजीपुर में भी भारत बंद का असर बुधवार को देखने को

मिला। यहां सड़क पर उतरकर प्रदर्शनकारियों ने बंद कराया। सड़क जाम किया गया जिससे वाहनों के परिचालन में बाधा आयी। लोग सड़क पर पैदल चलते दिखे। अपने सामानों के साथ यात्री पैदल ही चलते दिखे। वहीं महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों की कतार लग गयी।
हाजीपुर में बंद कराने उतरा संगठन
आरक्षण के मुद्दे को लेकर आहूत भारत बंद का असर हाजीपुर में बुधवार की सुबह दिखा। हाजीपुर में सड़क जाम किया गया है जिससे यातायात व्यवस्था बाधित है। दलित सेना और एससी-एसटी समर्थक सभी संगठनों ने आगजनी करके एनएच जाम किया। वहीं बड़ी तादाद में पुलिस की भी तैनाती सड़कों पर दिखी।
दरभंगा में दिखा भारत बंद का असर, ट्रेन का चक्का जाम किया
दरभंगा जंक्शन पर भीम आर्मी समेत कई पार्टियां भारत बंद को सफल बनाने उतरीं। दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन का चक्का जाम करके अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

UPSC को सीधी भर्ती रोकने का आदेश घमासान के बाद लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक

चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ
यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। पीएम मोदी के निर्देश पर लेटरल बहाली पर रोक लगा दी गई है। सीधी भर्ती का रोकने का फैसला लेते हुए विज्ञापन को रद्द करने को कहा गया है। इसको लेकर कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी को पत्र लिखा है। दरअसल, यूपीएससी ने बीते 17 अगस्त को एक विज्ञापन निकाला था जिसमें लेटरल एंट्री के जरिए 45 संयुक्त सचिव, उपसचिव और डायरेक्टर लेबल की भर्तियां होनी थी। इस विज्ञापन के सामने आने के बाद विवाद शुरू हो गया था। विपक्ष ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और सरकारी बहाली में आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ आंदोलन का बंद कही। विपक्ष के साथ साथ सरकार के



सहयोगी दल भी यूपीएससी के इस विज्ञापन को लेकर सवाल उठा रहे थे और इसको लेकर शीर्ष नेतृत्व से बात करने को कहा था। विपक्ष के साथ साथ गठबंधन में घमासान छिड़ता देख आखिरकार केंद्र सरकार ने यूपीएससी के इस विज्ञापन को रद्द करने का आदेश दे दिया है और यूपीएससी में किसी भी तरह की सीधी भर्ती पर रोक

लगाने को कहा है।
विवाद को बढ़ता देख खुद पीएम मोदी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और पीएम के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेन्द्र सिंह ने यूपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिखा है और तुरंत लेटरल बहाली के फैसले पर रोक लगाने को कहा है।

राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवार का किया ऐलान

चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ
पटना। इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी दिल्ली से आ रही है जहां बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पटना के रहने वाले सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा को बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। वही जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा को अपना उम्मीदवार

बनाया है। बता दें कि 7 राज्यों की 10 राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक हुई। जिसमें राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गयी। नामांकन के आखिरी दिन से एक दिन पहले आज बीजेपी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन

मनन कुमार मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। एनडीए ने दो राज्यसभा उपचुनाव सीटों के लिए उम्मीदवार के नामों की घोषणा आज कर दी है। मनन कुमार मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा 21 अगस्त को अंतिम दिन नामांकन पत्रा भरेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने दे दिया ये बड़ा निर्देश

कोलकाता कांड को लेकर बिहार में डॉक्टरों का आंदोलन: पटना के चार बड़े अस्पतालों में OPD सेवाएं ठप



चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ
पटना। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर पूरे देश में डॉक्टरों का आंदोलन तेज हो गया है। इस आंदोलन का खासा असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना के तार बड़े अस्पतालों की ओपीडी सेवा पिछले कई दिनों से ठप हो गई है। पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस और पटना एम्स में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। मंगलवार को भी डॉक्टरों ने इन अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद रखने का फैसला लिया है। पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस और

पटना एम्स में जूनियर रेजिडेंट की हड़ताल मंगलवार को भी जारी रहेगी। ऐसे में मंगलवार को इन अस्पतालों में न तो ओपीडी चलेगी और न ही पहले से निर्धारित सर्जरी ही हो सकेगी। सोमवार को भी इन अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर धरना पर बैठे रहे। पटना के सभी चार बड़े अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप होने से मरीजों की जान सांसत में पड़ गई है। डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवा को तो बाधित नहीं किया है लेकिन ओपीडी की सेवा पिछले कई दिनों से बंद है, जिससे दूर-दराज से इलाज कराने पटना पहुंचे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा

है। मरीज और उनके परिजन इलाज के लिए इन अस्पतालों में भटकते नजर आए। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पुलिस को सख्त निर्देश दे दिया है कि डॉक्टरों की मामूली शिकायत पर भी तुरंत एक्शन लिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि बिहार सरकार की पहली प्राथमिकता डॉक्टर हैं। सरकार के स्तर पर सभी जिलों के एसएसपी-एसपी को निर्देश दिया गया है कि डॉक्टर के साथ साथ किसी भी श्रेणी का स्वास्थ्यकर्मी अगर अपनी शिकायत दर्ज कराता है को उसपर तुरंत एक्शन लिया जाए।